झारखण्ड सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिति
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेस विज्ञप्ति

स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र (एचडब्ल्युसी) तैयार करने के लिए टीम बनायें जिलों के सिविल सर्जन : अभियान निदेशक, एनएचएम

2022 तक राज्य में 4340 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र शुरू करने का लक्ष्य

रांची, 11 जून, 2018: हमें 2022 तक राज्य के सभी 4340 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों को संचालित कर देना है इसलिए काम में तेजी लानी होगी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है और इसी के तहत इन केंद्रों का संचालन किया जायेगा। उक्त बातें अभियान निदेशक कृपानंद झा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) ने कही। श्री झा सोमवार को कैपिटल हिल में राज्य स्तरीय पदाधिकारी, परामर्शी, राज्य के सभी जिलों के सिविल सर्जनों और जिला कार्यक्रम प्रंबधक, जिला कार्यक्रम समन्वयक के लिए आयोजित कंप्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थकेयर (सी.पी.एच.सी) विषय पर आयोजित एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सबोधित कर रहे थे।

अभियान निदेशक कृपानंद झा ने कहा कि स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों में छह सेवायें आर.एम.एन.सी.एच प्लस ए और छह अन्य सेवायें ओरल, मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। इन केंद्रों में ब्रिज कोर्स पूरा करनेवालों को सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (सीएचओ) के रूप में नियुक्त किये जायेंगे। इसेक अलावा जिला सदर अस्पतालों और अनुमंडल अस्पतालों में इंफ्रास्टक्चर तैयार करना होगा ताकि इन अस्पतालों में भी ब्रिज कोर्स शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि फेसिलिटी और सेवाओं में हमें गैप आइडेंटिफाइ करना होगा। श्री झा ने कहा कि हमें केंद्र और राज्य सरकार पर निर्भरता कम करते हुए उपायुक्त और विधायक निधि के मद का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य केंद्रों में अगर बिजली और पानी की समस्या है तो उपायुक्त स्तर पर होने वाली बैठक में इन मामलों का समाधान करें। अभियान निदेशक ने कहा कि जिन स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र बनाया जाना है वहां की छोटी छोटी समस्याओं को जिला स्तर पर निपटें और यदि समस्या राज्य स्तर से सुलझ सकती है तो ऐसी समस्याओं को राज्य पदाधिकारियों के पास भेजें। श्री झा ने कहा कि जिला स्तर पर सिविल सर्जन टीम बनायें और इस टीम को जिम्मेवारी सौंपकर उसकी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का प्रदर्शन खराब होने पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) जिम्मेवार माने जायेंगे। श्री झा ने कहा कि कुछ जिलों में एनसीडी

और एनपीसीडीसीएस कार्यक्रम चल रहा है इन कार्यक्रमों को टेक ओवर करते हुए सफल बनाना होगा। अभियान निदेशक ने कहा कि हमें सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को साफ सुथरा रखना होगा और वहां बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवानी होंगी।

लोगों को संबोधित करते हुए निदेशक प्रमख, स्वास्थ्य सेवायें डॉ सुमंत मिश्रा ने कहा कि सरकार द्वारा तीन स्तरों पर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करवायी जाती है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में लोगों को गुणवत्ता युक्त सेवायें मिल सके इसके लिए बेहतर तैयारी करनी होगी। कुछ कठिनाईयां हैं लेकिन उन्हें चुनौती के रूप में लेना होगा। जो भी कमियां हैं उन्हें दूर कर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाया जायेगा।

इस कार्यक्रम में आयुष्मान भारत के स्टेट नोडल पदाधिकारी डॉ एस.के. सिंह, डॉ ललित पाठक, डॉ बिरेंद्र प्रसाद, ज्वाला प्रसाद, नीता कुजूर और सभी जिलों के सिविल सर्जन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और राज्य परामर्शी उपस्थित थे।

स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र

नैशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के तहत भारत सरकार ने देश भर के **एक लाख पचास हजार** स्वास्थ्य उपकेंद्रों को स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र के रूप में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र को प्रखंड स्तर पर पहले स्तर के रेफरल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रा से जोड़कर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है।

झारखण्ड राज्य के लिए पिछले साल 12 स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र (हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर) चिन्हित किए गये थे जिनमें से नौ केंद्रों पर सेवाएं दी जा रही हैं और बाकी के तीन केंद्रों में जल्द ही सेवा शुरू कर दी जायेगी। रांची जिले के नौ, सिमडेगा जिले के दो और गुमला से एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र में सेवायें दी जायेंगी। इन केन्द्रों में 12 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किये गये हैं। आयुष्मान भारत के साथ साथ विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान के तहत अगस्त 2018 तक प्रत्येक जिलों के दो उपकेन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र के अपग्रेडेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

मार्च 2019 तक राज्य भर में 711 एच.एस.सी, 33 पीएचसी और 32 यु.पी.एच.सी के स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर दी जायेंगी। इस सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए दो प्रोग्राम स्टडी सेंटर के माध्यम से 41 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इग्नू के पदाधिकारियों ने राज्य के पांच और प्रोग्राम स्टडी सेंटर का निरीक्षण किया है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजना के तहत स्वास्थ्य उपकेन्द्रों (एच.एस.सी) को अपग्रेड करते हुए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जाना है। इन केन्द्रों पर निम्नलिखित सेवाऐं उपलब्ध करवाने की योजना है –

1. केयर इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ।
2. नियोनेटल एंड इनफेंट हेल्थ केयर सर्विसेज।
3. चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट हेल्थकेयर सर्विसेज इनक्लुडिंग इम्युनाइजेशन।
4. फेमिली प्लानिंग, कोन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज एंड अदर्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज।
5. मैनेजमेंट ऑफ कॉमन कम्युनिकेबल डिसिजेस एंड जेनरल आउट पेसेंट केयर फॉर एक्युट सिंपल इलनेस एंड माइनर एलमेंटस्।
6. मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिसिजेसः नैशनल हेल्थ प्रोग्राम।
7. प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नन कम्युनिकेबल डिसिजेस।
8. स्क्रीनिंग एंड बेसिक मैनेजमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एलमेंट्स।
9. केयर फॉर कामन अथ्यालमिक एंड इ.एन.टी प्राब्लम्स।
10. बेसिक ओरल हेल्थ केयर।
11. गिरियाटरिक एंड पालिएटिव हेल्थ केयर सर्विसेज।
12. ट्राउमा केयर एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज।

प्रिवेंशन, स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नन कम्युनिकेबल डिसिजेस के अन्तर्गत –हाइपरटेंशन, डायबिटिज, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का पॉपुलेशन बेस्ड एनसीडी स्क्रिनिंग की जाती है।

<u>स्टेट रॉल आउट प्लान</u>

वित्त वर्ष	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	शहरी पीएचसी
2018-19	711	33	32
2019-20	1080	99	20
2020-21	1127	99	0
2021-22	1040	99	0

नोडल ऑफिसर
आई0 ई0 सी0 कोषांग